कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो वेतन उनको प्राप्त होना चाहिए था, वह उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। एक तरफ तो लखनऊ चिकित्सा विश्वविद्यालय में वहां के डॉक्टर्स को वह वेतन दिया जा रहा है, लेकिन बाकी के मेडिकल कॉलेज चाहे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आगरा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कानपुर मेडिकल कॉलेज हो, वहां के डॉक्टर्स को नया वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि वहां के सभी डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया और हड़ताल पर चले गए हैं। मरीज़ भाग रहे हैं, कुछ मरीज़ मर गए हैं। इमरजेंसी में गए, दवा नहीं हुई। चाहे कानपुर के मेडिकल कॉलेज में गए, उनकी मृत्यु हो गई, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में तीन लोगों की मृत्यु हुई। इमरजेंसी में गए, उनको कोई देखने वाला नहीं रहा, संत कबीरनगर अस्पताल में गए, कोई देखने वाला नहीं रहा, वहां उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार आगरा में ...तो एक-एक अस्पताल के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर यह पता चला है कि वहां जो मरीज़ जा रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। हालत बद से बदतर होती जा रही है और वहां के शासन के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। संवेदनशून्यता इतनी अधिक बढ़ गई है कि आम मरीज़ यह अनुभव करने लगा है कि हम कहां जाएं? गरीब मरीज़ चिकित्सा न प्राप्त होने के कारण त्रस्त हो रहा है और जब बाहर आ रहा है, घर पर भी, तो ठीक से दवा न मिल पाने के कारण उसकी दुर्दशा हो रही है। तो ऐसी हालत में जबकि हालत बद से बदतर होती जा रही है, केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और राज्य सरकार के द्वारा जो विभेदकारी व्यवहार डॉक्टर्स के प्रति अपनाया जा रहा है, उसको भी समाप्त करने की जरूरत है। लखनऊ चिकित्सा विश्वविद्यालय के जूनियर डॉक्टर्स को जो वेतन प्राप्त हो रहा है, बाकी के लोगों को भी वह प्राप्त हो, यह व्यवस्था करने की भी जरूरत है और अगर पैसे की कमी है, तो मैं तो आग्रह करूंगा कि अभी यहां के स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि मोबाइल वैन वगैरह को अभी राज्य सरकार मांग नहीं रही है, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इसमें बढ़कर हस्तक्षेप करते हुए जो भी कमी हो, उसको पूरा करने का यहां के लोग प्रयत्न करें, तो वह ज्यादा अच्छा होगा। वहां तत्काल जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त होनी ही चाहिए, किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करके करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बलबीर पुंज (उड़ीसा) **:** सर, मैं इससे स्वयं को एसोसिएट करता हूं।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) **:** सर, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री नन्द किशोर यादव (उत्तर प्रदेश) **:** सर, मैं भी अपने आप को इससे एसोसिएट करता हूं।

श्री उपसभापति : ठीक है, सभी एसोसिएट करते हैं।

Plight of Sikh refugees in Pakistan

सरदार तरलोचन सिंह (हरियाणा) : चेयरमैन साहब, पिछले सैशन में मैंने यह मसला उठाया था, जो आज मैं दोबारा उठा रहा हूं। श्री अहलुवालिया और श्री करीमपुरी, दोनों ने मेरे साथ खड़े होकर आवाज़ उठाई थी, मगर आज बड़े दुख के साथ मैं दोबारा यह कह रहा हूं कि कल मैंने पार्लियामेंट में इसी issue पर एक unstarred question पूछा था और जो जवाब मुझे Ministry of External Affair से मिला है, उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि हमारी जो Ministry of External Affairs है, उसका attitude towards Sikh refugees क्या है ! पाकिस्तान में पहले जज़िया उन सिख लोगों से लिया गया और जब जज़िए की खबर आई, तो करीब दो-तीन हज़ार लोगों को दो करोड़ रुपए जज़िया देना पड़ा और उसके बाद उनके घर जला दिए गए और वे जाकर पंजा साहब गुरुद्वारे में रहे। जब Ministry of External Affairs से मैंने यह सवाल पूछा, तो जवाब यह मिला है कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि दो हज़ार सिख वहां से निकाले गए और गुरुद्वारे में रह रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या भारत सरकार का खुद कोई अफसर या MEA का कोई कर्मचारी वहां गया? तो जवाब मिला -

नहीं, it means कि भारत सरकार रिफ्यूजियों के लिए, जिनके घर जलाए गए, जिनसे जज़िया लिया गया, यह मिनिस्ट्री उनके पास जाने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर मेरा क्वेश्चन था - Whether any aid has been sent by the Government of India? जवाब मिला - No. आज अभी इस हाउस में मंत्री जी बैठे हैं, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं....हम मानते हैं कि पाकिस्तान में independent government है, sovereign government, तो क्या ऐसे मसले जो कि humanitarian हों...... जज़िया एक ऐसी गंदी बात है कि अगर कोई गैर मुस्लिम वहां रहे तो वह टैक्स पे करे। यह आज से दो-तीन सौ साल पहले भारत में था। क्या आज यह जज़िया allowed है? मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि या तो सरकार पार्लियामेंट के मुस्लिम मैंबर्स वहां भेजे जो वहां जाकर इस मसले को देखें। कम से कम वहां गरीबों से जज़िया वापस कराया जाए, उनकी rehabilitation करायी जाए। ये लोग गुरूद्वारे में रह रहे हैं। दो हजार लोग पंजा साहब में और एक हज़ार लोग पेशावर में गुरूद्वारे में रह रहे हैं। क्या एम.ई.ए. की इस संबंध में कोई ड्यूटी है? अभी तक कोई ऑफिशियल दिल्ली से वहां पर नहीं गया। मैं मानता हूं कि श्रीलंका में बहुत कुछ हुआ, बहुत से मिनिस्टर्स वहां पर गए। क्या वहां पर कोई वोट बैंक की पॉलिसी थी? वह भी genuine था। लेकिन पाकिस्तान में सिखों के साथ कुछ अन्याय होता है तो हम उसे भूल जाते हैं। आज मैं आपके माध्यम से सारे हाउस के सामने कहना चाहता हूं कि यह बहुत pathetic केस है, हमारे लोग तीन महीने से गुरूद्वारे में बैठे हैं, दो करोड़ रुपया जज़िया दे चुके हैं, उन्हें घरों में वापस नहीं भेजा जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सुनने के लिए, कोई sympathy का word देने के लिए तैयार नहीं है, यही मेरी आपसे अर्ज है।

SHRI BALBIR PUNJ (Orissa): Sir, it is a very serious matter. ...*(Interruptions)*... The Government of India has not done anything. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): In the matter of Jajia the Government has not done anything. ...*(Interruptions)*...The Government owes an explanation to the country, Sir. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the sentiments expressed by the hon. Members.

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, the Chair should give a direction to the Government. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Special Mentions. ...*(Interruptions)*... I cannot ask the Government to respond. ...*(Interruptions)*... Special Mentions. ...*(Interruptions)*... Shri Santosh Bagrodia. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : केवल असोसिएट करिए।..(व्यवधान)..

SHRI BALBIR PUNJ: Sir, the Government should respond....*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : सरकार सुन रही है, आप बोल रहे हैं। यह ज़ीरो ऑवर है, मैंने कल बता दिया था। I cannot ask the Government to respond.

श्री रवि शंकर प्रसाद : यह बहुत ही गंभीर विषय है, गवर्नमेंट का रिस्पाँस आना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : सर, हम माननीय सदस्य से स्वयं को संबंद्ध करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Special Mentions. Shrimati Brinda Karat. Not present. Shri Santosh Bagrodiaji. ...*(Interruptions)*... Just lay it. ...*(Interruptions)*...

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Why should it be laid only, Sir? It is an important issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want to read it, you can do so at five o' clock. If you want to lay it, you can do it right now. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): What you say is right but I request you that this practice should be as much as possible be used only...*(Interruptions)*... It has become a rule. So, let us not make it a rule. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not a rule.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I am talking only about future; today it is all right. ...*(Interruptions)*... Sir, I lay my Special Mention on the Table of the House.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, subject matter of my Special Mention is very important, so I must speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You just lay it. Otherwise, you can do so after five o' clock. I do not mind it. ...*(Interruptions)*...

SPECIAL MENTIONS

Concern over racism against Indians abroad

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, I rise to commend the attention of this House to recent incidents of racist violence against Indian students and professionals in different countries. Even as the Government has taken up the issue with the Australian Government, and despite the concerns shared by them, the attacks have continued. The Australian authorities continue to live in denial, unable to see a definite racist pattern, they consider such attacks as part of urban life. The advisories that have appeared in media in the wake of racist incidents suggest that Indians attracted such attacks due to their inability to assimilate in local community. One wonders if suggestions are being made for forced assimilation by subsuming cultural identities. Some have suggested recession in local economy as the cause behind racial attacks. Therefore, these incidents must also warn us of the limitations of current free trade regime that champions only the free movement of goods and capital without addressing the issue of free movement of professionals and students who carry their ideas, skills and cultures along. Any dislocation in economy exposes the violent divisions among the communities. Essentially, our Government has the responsibility to safeguard the interests of our citizens. Lack of career prospects has compelled our students to move abroad. The pending proposal to allow foreign universities to open their campuses in India will give our students an access to quality higher education at comparatively affordable price without exposing them to racial hostility. I support this policy and ask the Government to expedite the action.

Demand to settle grievances of contract labourers in Neyveli Lignite Corporation

SHRI N. BALAGANGA (Tamil Nadu): Sir, the Neyveli Lignite Corporation which was established in 1954 and which is one of the profitable PSUs, having three mines, three thermal